

जून 2026
योजना
पत्रिका का सारांश

**नक्सल-मुक्त
भारत**

विषय 1: नक्सल-मुक्त भारत: एक ऐतिहासिक उपलब्धि (NAXAL-FREE INDIA: A HISTORIC ACHIEVEMENT)

वामपंथ उग्रवाद (LWE) का उन्मूलन, मार्च 2026 की घोषणा, विचारधारा बनाम विकास, रेड कॉरिडोर का पतन, UPA काल की नीतिगत अस्पष्टता बनाम 2014 के बाद की आक्रामक रणनीति, 'ऑल-एजेंसी अप्रोच' और सुरक्षा कैंप (लेखक: अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री)

नक्सल-मुक्त भारत विजन: “नक्सलवाद गरीबी के कारण नहीं फैला; बल्कि नक्सलवाद के कारण ही इस पूरे क्षेत्र में वर्षों तक गरीबी बनी रही, जिसे मोदी सरकार अब समाप्त कर रही है। यह उपलब्धि स्पष्ट नीति, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के असाधारण साहस का परिणाम है।” — अमित शाह

1. कार्यकारी सारांश एवं ऐतिहासिक उपलब्धि

जून 2026 के 'योजना' अंक (विषय: नक्सल-मुक्त भारत) के पहले आलेख 'नक्सल-मुक्त भारत: एक ऐतिहासिक उपलब्धि' (Naxal-Free India: A Historic Achievement) में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्लेषण किया है कि कैसे मार्च 2026 तक देश को वामपंथ उग्रवाद (Left-Wing Extremism - LWE) से पूरी तरह मुक्त कर लिया गया है। यह उपलब्धि पिछले पांच दशकों से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती बने खतरे के अंत का प्रतीक है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि यह ऐतिहासिक सफलता स्वतः नहीं आई; इसके पीछे एक स्पष्ट नीति, अडिग राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों का असाधारण साहस निहित है। UPA काल की नीतिगत अस्पष्टता और वैचारिक नरमी से विपरीत, 2014 के बाद से सरकार ने 'गोली का जवाब गोली से' और विकासोन्मुखी रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया।

2. विचारधारा बनाम विकास: नक्सलवाद की जड़ें

- झूठा नैरेटिव:** दशकों तक नक्सलियों और उनके समर्थकों ने यह झूठा प्रचार किया कि वे आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वास्तव में यह विकास की मांग नहीं बल्कि एक विध्वंसक वैचारिक लड़ाई थी।

- गरीबी का कारण:** नक्सलवाद गरीबी के कारण नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद ने ही इन क्षेत्रों में विकास को रोककर गरीबी को बनाए रखा। 1960 के दशक में नक्षलबाड़ी, बस्तर, सहरसा और बलिया में साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय समान थी, लेकिन नक्सलवाद केवल उन्होंने घने जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में पनपा जहां राज्य की पहुंच कम थी।
- विनाशकारी रणनीतियां:** नक्सलियों ने आदिवासियों को मुख्यधारा से दूर रखने के लिए स्कूल, बैंक, और चिकित्सा केंद्रों को जलाया तथा विकासवात्मक कार्यों में बाधा डाली।

3. रेड कॉरिडोर और UPA काल की नीतिगत अस्पष्टता

- रेड कॉरिडोर का आतंक:** 12 राज्यों में फैला 17% भूभाग और 20 करोड़ की आबादी इसकी गिरफ्त में थी। 20,000 युवाओं की मौत, 3,500+ सुरक्षाकर्मियों का बलिदान, जहानाबाद जेल हमला, और ₹240 करोड़ का वार्षिक 'जनताना टैक्स' वसूली इसकी भयावहता दर्शाती है।
- UPA काल की कमियां:** 2004 में CPI (Maoist) का गठन हुआ। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती माना, लेकिन ठोस कार्रवाई का अभाव रहा। 'सलवा जुडूम' के स्वयंसेवकों के हथियार छीनकर उन्हें unprotected छोड़ दिया गया, जिससे नीतिगत laxity और वैचारिक सहानुभूति ने इस समस्या को और बढ़ाया।

4. 2014 के बाद नीतिगत बदलाव और सुरक्षा सफलताएं

- ऑल-एजेंसी अप्रोच:** एनआईए (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क और सहायता प्रणालियों पर कड़ा प्रहार किया गया।
- सुरक्षा कैंपों का विस्तार:** 126 से घटकर नक्सल प्रभावित जिले केवल 2 रह गए हैं। पिछले 6 वर्षों में 406 नए CAPF कैंप और 596 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए।
- निर्णायक सैन्य अभियान:** 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' जैसे अभियानों के तहत ड्रोन सर्विलांस, उपग्रह इमेजरी और AI-आधारित डेटा विश्लेषण का उपयोग करके शीर्ष केंद्रीय समिति (Central Committee) और पोलित ब्यूरो के नेतृत्व का लगभग पूर्ण सफाया कर दिया गया।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: नक्सल विरोधी रणनीति, पैमाना और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका नक्सलवाद के खिलाफ अपनाई गई रणनीतियों, UPA और वर्तमान शासन के अंतर तथा राष्ट्रीय प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

रणनीतिक आयाम	UPA शासनकाल (पूर्व-2014)	वर्तमान शासनकाल (2014-2026)	राष्ट्रीय व सुरक्षा प्रभाव
नीतिगत दृष्टिकोण	नीतिगत अस्पष्टता, वैचारिक नरमी और आत्मसमर्पण के दबाव का अभाव	स्पष्ट नीति, 'गोली का जवाब गोली' और शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance)	सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा और राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति
सुरक्षा ढांचा	सीमित कैंप, सुस्त खुफिया तंत्र और सुरक्षा वैक्यूम	350+ नए सुरक्षा कैंप, फोर्टिफाइड थाने और उन्नत तकनीक (ड्रोन/AI)	दुर्गम क्षेत्रों में राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा की बहाली
नेतृत्व और नेटवर्क	नक्सली नेतृत्व का विस्तार और मजबूत वित्तीय नेटवर्क	केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के शीर्ष नेतृत्व का पूर्ण खात्मा	नक्सलियों की कमान और वैचारिक पकड़ पूरी तरह ध्वस्त
विकास और पुनर्वास	विकास कार्यों में भारी बाधा और उपेक्षा	12,000+ किमी सड़कें, 5,000 मोबाइल टावर, EMRS और आकर्षक आत्मसमर्पण नीति	मुख्यधारा में वापसी और बस्तर में शांति व विकास का उदय

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (आंतरिक सुरक्षा — आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां और उनका प्रबंधन, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा का समन्वय)

- वामपंथ उग्रवाद का खात्मा और मॉडल: यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे एक व्यापक 'ऑल-एजेंसी अप्रोच', आधुनिक तकनीक, सुदृढ़ खुफिया तंत्र और केंद्र-राज्य समन्वय के माध्यम से दशकों पुराने नक्सली खतरे को समाप्त किया गया।
- सुरक्षा और विकास का समन्वय: सड़क निर्माण, संचार संपर्क (मोबाइल टावर), शिक्षा (EMRS) और पुनर्वास नीतियों के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन की बहाली के महत्व को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा नक्सल-मुक्त भारत दृष्टिकोण: “नक्सलवाद गरीबी के कारण नहीं फैला; बल्कि नक्सलवाद के कारण ही इस पूरे क्षेत्र में वर्षों तक गरीबी बनी रही, जिसे मोदी सरकार अब समाप्त कर रही है।” — अमित शाह

विषय 2: संघर्ष से प्रगति की ओर: छत्तीसगढ़ का रूपांतरण (FROM CONFLICT TO PROGRESS: CHHATTISGARH'S TRANSFORMATION)

बस्तर क्षेत्र का परिवर्तन, DRG (जिला रिजर्व गार्ड) की भूमिका, आधुनिक तकनीक व केंद्र-राज्य समन्वय, आर्थिक मोर्चे पर प्रहार (तेंदू पत्ता नीति), मानवीय पुनर्वास (लियोर ओयना कार्यक्रम, बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडम), और नियदा नेल्ला नार (Niyada Nella Nar) पहल (लेखक: विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार)

छत्तीसगढ़ परिवर्तन विजन: “आज छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर, नक्सली हिंसा और असुरक्षा के लंबे दौर से निकलकर शांति, विकास और सुशासन के नए युग में प्रवेश कर रहा है। सुरक्षा बलों के अद्वितीय साहस और राजनीतिक इच्छाशक्ति से यह ऐतिहासिक सफलता मिली है।” — विजय शर्मा

1. कार्यकारी सारांश एवं बस्तर का कायाकल्प

जून 2026 के 'योजना' अंक के दूसरे आलेख 'संघर्ष से प्रगति की ओर: छत्तीसगढ़ का रूपांतरण' (From Conflict to Progress: Chhattisgarh's Transformation) में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने विश्लेषण किया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य ने बस्तर क्षेत्र को नक्सलवाद के खौफ से मुक्त कर विकास और सुशासन की राह पर अग्रसर किया है।

परिवर्तन आयाम	मुख्य पहल / रणनीति	कार्यान्वयन व पैमाना	सामाजिक व आर्थिक प्रभाव
सुरक्षा और DRG बल	स्थानीय युवाओं की भर्ती और तकनीकी एकीकरण (ड्रोन, स्निपर्स)	बस्तर के दुर्गम जंगलों में सटीक और शून्य-हताहत अभियान	नक्सली गढ़ों का पतन और सुरक्षा बलों में स्थानीय विश्वास
आर्थिक मोर्चेबंदी	तेंदू पत्ता व्यापार का राष्ट्रीयकरण और वनोपज आय प्रबंधन	नक्सलियों की अवैध लेवी और फंडिंग स्रोतों पर रोक	नक्सलियों की आर्थिक रीढ़ टूटी और आदिवासियों को सीधा लाभ

लेखक रेखांकित करते हैं कि लगभग चार दशकों तक नक्सलवाद ने बस्तर को गहरे जख्म दिए, हजारों मासूमों की जान ली और विकास के सभी रास्ते रोक दिए। लेकिन अब केंद्र और राज्य के मजबूत समन्वय, सुरक्षा बलों के पराक्रम और आधुनिक तकनीक के उपयोग से बस्तर में शांति और प्रगति का नया सवेरा हुआ है।

2. सुरक्षा रणनीति और DRG (जिला रिजर्व गार्ड) की भूमिका

- स्थानीय युवाओं की सहभागिता:** DRG (District Reserve Guard) में केवल 10-15% आत्मसमर्पित नक्सली हैं, जबकि शेष बस्तर के स्थानीय युवा हैं जो वहां की संस्कृति, बोलियों, जंगलों और भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह परिचित हैं।
- तकनीकी एकीकरण:** गृह मंत्रालय के निर्देशन में ITBP, NSG, NTRO, DRDO और ISRO जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने ड्रोन सर्विलांस, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रैकिंग और अत्याधुनिक हथियार (जैसे AK-47, स्निपर्स) उपलब्ध कराए, जिससे बिना किसी हताहत के सटीक अभियान संचालित हुए।

3. आर्थिक मोर्चे पर प्रहार और मानवीय पुनर्वास

- लघु वनोपज नीति:** तेंदू पत्ता जैसे प्रमुख वनोपज को निजी ठेकेदारों से मुक्त कर सरकारी एजेंसी के अधीन लाया गया, जिससे नक्सलियों को मिलने वाला आर्थिक फंड बंद हुआ और आदिवासियों को सीधा लाभ मिला।
- मानवीय पुनर्वास नीति:** आत्मसमर्पित नक्सलियों को लाल कालीन बिछाकर मुख्यधारा में स्वागत किया गया। उन्हें आधार, आयुष्मान और राशन कार्ड के साथ 'लियोर ओयना' (युवा आमंलण) कार्यक्रम के तहत रायपुर व विधानसभा की सैर कराई गई।
- पूर्व नक्सलियों की नई शुरुआत:** कभी हथियार उठाने वाले लक्ष्मण पोयम और पूलमती मंडावी जैसे कैडरों ने अब 'पंडुम कैफे' के जरिए समाज में सम्मानजनक आजीविका अपना ली है।

4. शिक्षा, स्वास्थ्य और 'नियदा नेल्ला नार' पहल

- स्कूलों का पुनरुद्धार:** सुकमा और बीजापुर (जैसे बेचपाल, कवाड़गांव) में पिछले 20 वर्षों से बंद पड़े 120+ स्कूलों को दोबारा खोला गया। बीजापुर के ग्रामीण गुडमा गांव के अंकित सकनी ने UPSC परीक्षा पास कर मिसाल कायम की।
- नियदा नेल्ला नार (मेरा अच्छा गांव):** सुरक्षा कैंपों के इर्द-गिर्द 144 ग्राम पंचायतों और 500+ गांवों में 17 विभागों की 25 व्यक्तिगत व 18 सामुदायिक योजनाओं को संतृप्त किया गया।
- सुकमा के पूर्व नक्सली हिड़मा के गांव में बदलाव:** कभी आतंक का पर्याय रहे पूर्व गांव में सुरक्षा कैंप खुलने के बाद पहली बार मतदान हुआ, सड़क बनी, गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया और राशन दुकान खुली।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: छत्तीसगढ़ परिवर्तन के आयाम और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे, पुनर्वास और विकासमक बदलावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

मानवीय पुनर्वास	नई आत्मसमर्पण नीति, 'लियोर ओयना' और पंडुम कैफे	हजारों कैदों की घर वापसी और समाज में सम्मानजनक पुनरुद्धार	भय के माहौल से मुक्ति और मुख्यधारा में सफल एकीकरण
शिक्षा और सुशासन	बंद स्कूलों का पुनरुद्धार और 'नियदा नेल्ला नार' पहल	120+ स्कूल पुनः शुरू और 500+ गांवों में योजनाओं का विस्तार	बच्चों को शिक्षा का अधिकार और सुदूर गांवों तक शासन की पहुंच

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख आंतरिक सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास और जनजातीय कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (आंतरिक सुरक्षा — उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भूमिका, विकास और शासन के माध्यम से संघर्ष समाधान)

- **बस्तर का रूपांतरण और DRG मॉडल:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बलों (DRG) में शामिल करने और केंद्र-राज्य के तकनीकी समन्वय ने बस्तर में अभूतपूर्व सफलता दिलाई है?
- **शिक्षा और सुशासन की पुनःस्थापना:** 'नियदा नेल्ला नार' पहल और बंद स्कूलों के पुनरुद्धार के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन और विश्वास बहाली के मॉडल को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा छत्तीसगढ़ परिवर्तन दृष्टिकोण: "सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों को जीतना नहीं, बल्कि वर्षों से हाशिए पर रहे लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। भय के साये में विकास का सपना देखना बेमानी है।" — विजय शर्मा

विषय 3: नक्सल-मुक्त भारत: एक सामरिक बदलाव (NAXAL-MUKT BHARAT: A STRATEGIC TURNAROUND)

वामपंथ उग्रवाद (LWE) के खिलाफ समन्वित राज्यकला (Coordinated Statecraft), MHA की रणनीतिक भूमिका और SAMADHAN सिद्धांत, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) व CAPF की भूमिका, राज्यों की क्षमता निर्माण (SRE और SIS), और वित्तीय नेटवर्क पर प्रहार (लेखक: कुलदीप सिंह, पूर्व डीजी, CRPF और NIA; सुरक्षा सलाहकार, मणिपुर सरकार)

सामरिक बदलाव विजन: "नक्सल-मुक्त भारत की कहानी केवल सैन्य या पुलिस सफलताओं की नहीं है। यह समन्वित राज्यकला की कहानी है। यह दर्शाती है कि कैसे राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय, पेशेवर सुरक्षा अभियान और विकासात्मक प्रतिबद्धता एक साथ मिलकर लंबे समय से चले आ रहे विद्रोह का सामना कर सकती है और उसे उलट सकती है।" — कुलदीप सिंह

1. कार्यकारी सारांश एवं समन्वित राज्यकला

जून 2026 के 'योजना' अंक के आलेख 'नक्सल-मुक्त भारत: एक सामरिक बदलाव' (Naxal-Mukt Bharat: A Strategic Turnaround) में CRPF और NIA के पूर्व महानिदेशक तथा वर्तमान में मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने विश्लेषण किया है कि कैसे गृह मंत्रालय (MHA) के रणनीतिक नेतृत्व, संस्थागत समन्वय और शून्य-सहनशीलता की नीति ने वामपंथ उग्रवाद (LWE) को जड़ से उखाड़ फेंका।

लेखक रेखांकित करते हैं कि नक्सल-मुक्त भारत का लक्ष्य केवल एक सुरक्षा उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह LWE-प्रभावित क्षेत्रों में शासन बहाल करने, विकास

का विस्तार करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। यद्यपि कानून और व्यवस्था एक राज्य का विषय है और राज्य पुलिस बलों ने अभियानों का नेतृत्व किया, फिर भी MHA ने एक रणनीतिकार, समन्वयक और फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाई।

2. SAMADHAN सिद्धांत और सामरिक रणनीतियां

गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'SAMADHAN' सिद्धांत ने इस अभियान को स्पष्ट दिशा दी:

- S - Smart Leadership (स्मार्ट नेतृत्व)
- A - Aggressive Strategy (आक्रामक रणनीति)
- M - Motivation and Training (प्रेरणा और प्रशिक्षण)
- A - Actionable Intelligence (कार्यान्वयन योग्य खुफिया जानकारी)
- D - Dashboard-based KRAs and KPIs (डैशबोर्ड-आधारित मुख्य परिणाम और प्रदर्शन संकेतक)
- H - Harnessing Technology (प्रौद्योगिकी का उपयोग)
- A - Action Plan for Each Theatre (प्रत्येक थिएटर के लिए कार्ययोजना)
- N - No access to Financing (वित्तपोषण तक कोई पहुंच नहीं)।

3. फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) और CAPF की भूमिका

- **सुरक्षा कैंपों का जाल:** उग्रवादियों के गढ़ों में 350 से अधिक सुरक्षा कैंप (जैसे DRG, C-60, SOG और जगुआर के साथ संयुक्त रूप से) स्थापित किए गए, जिससे नक्सलियों के लिए सुरक्षा वैक्यूम समाप्त हो गया।
- **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF):** CRPF (कोबरा कमांडो सहित), BSF, ITBP और SSB ने उग्रवादियों के खिलाफ अभियानों में रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया, दुर्गम वनों में घुसपैठ की और पुलिस बलों को सामरिक समर्थन दिया।

4. राज्यों की क्षमता निर्माण और वित्तीय प्रहार

- **वित्तीय सहायता व आधुनिकीकरण:** पिछले 11 वर्षों में सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) में 155% की वृद्धि की गई (₹3,371 करोड़ जारी)। विशेष बुनियादी ढांचा योजना (SIS) के तहत ₹371 करोड़ और फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (FPS) के लिए ₹620 करोड़ मंजूर किए गए।
- **वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना:** गृह मंत्रालय के भीतर दो बहु-विषयक समूहों (MDGs) की स्थापना की गई, जिन्होंने माओवादियों के वित्तीय संसाधनों पर कड़ा प्रहार करते हुए लगभग ₹40 करोड़ की संपत्ति जब्त की।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: सामरिक बदलाव के आयाम और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका कुलदीप सिंह द्वारा विश्लेषित सामरिक बदलाव, CAPF की भूमिका और परिणामों का विवरण प्रस्तुत करती है:

सामरिक आयाम	प्रमुख नीतिगत व ऑपरेशनल पहल	कार्यान्वयन पैमाना व मेट्रिक्स	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव
सामरिक नीति (SAMADHAN)	MHA द्वारा शून्य-सहनशीलता और बहुआयामी रणनीति का क्रियान्वयन	मार्च 2026 तक CPI (Maoist) के शीर्ष नेतृत्व का लगभग पूर्ण सफाया	रणनीतिक सुसंगतता और उग्रवाद के कमांड ढांचे का पतन
फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs)	उग्रवादियों के गढ़ों के भीतर संयुक्त सुरक्षा कैंपों की स्थापना	350+ रणनीतिक कैंप और विशेष कमांडो यूनिटों की तैनाती	सुरक्षा वैक्यूम का अंत और विकास कार्यों के लिए सुरक्षित मार्ग
राज्य क्षमता निर्माण	SRE, SIS और फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के लिए वित्तीय अनुदान	₹3,371 करोड़ SRE और ₹620 करोड़ फोर्टिफाइड थानों हेतु स्वीकृत	राज्य पुलिस बलों की ऑपरेशनल आत्मनिर्भरता और मारक क्षमता
वित्तीय नाकाबंदी	MHA के बहु-विषयक समूहों (MDGs) द्वारा फंडिंग पर प्रहार	माओवादी वित्तीय नेटवर्क की पहचान और ₹40 करोड़ की जब्ती	उग्रवादियों की रसद, हथियार और सांगठनिक रीढ़ टूटी

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख आंतरिक सुरक्षा, पुलिस सुधार और आतंकवाद/उग्रवाद प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (आंतरिक सुरक्षा — उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भूमिका, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का समन्वय, और «समग्र राज्यकला» का मॉडल)

- समन्वित राज्यकला और SAMADHAN मॉडल:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे MHA के रणनीतिक नेतृत्व, CAPF (CRPF/COBRA) की ऑपरेशनल रीढ़ और राज्य पुलिस के स्थानीय कौशल ने मिलकर एक सफल काउंटर-इंसर्जेंसी मॉडल प्रस्तुत किया है।
- संस्थागत समन्वय और वित्तीय नाकाबंदी:** उग्रवादियों के वित्तीय तंत्र (MDGs) को ध्वस्त करने और राज्यों की क्षमता निर्माण (SRE/SIS) के महत्व को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा सामरिक बदलाव दृष्टिकोण: नक्सल-मुक्त भारत की कहानी केवल सैन्य या पुलिस सफलताओं की नहीं है। यह समन्वित राज्यकला की कहानी है। यह दर्शाती है कि कैसे राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय, पेशेवर सुरक्षा अभियान और विकासात्मक प्रतिबद्धता एक साथ मिलकर लंबे समय से चले आ रहे विद्रोह का सामना कर सकती है।

विषय 4: LWE उन्मूलन के लिए «समग्र सरकार» (WHOLE-OF-GOVERNMENT) दृष्टिकोण

वामपंथ उग्रवाद (LWE) की पृष्ठभूमि, 1967 नक्षलबाड़ी से लेकर CPI (Maoist) का गठन (2004), 2009-10 में हिंसा का चरम, राष्ट्रीय नीति और एक्शन प्लान (2015) के चार प्रमुख स्तंभ (सुरक्षा, विकास, अधिकार व लोक-आउटरीच), और सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी (लेखक: राजीव कुमार, संयुक्त सचिव - LWE, गृह मंत्रालय)

समग्र सरकार विजन: “30 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में घोषणा की कि हम पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। सुरक्षा और विकास के समन्वित प्रयासों से यह असंभव लगने वाला लक्ष्य संभव हुआ है।” — राजीव कुमार

1. कार्यकारी सारांश एवं LWE की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जून 2026 के «योजना» अंक के तीसरे आलेख «LWE उन्मूलन के लिए «समग्र सरकार» (Whole-of-Government) दृष्टिकोण» (Whole-of-Government Approach for LWE Eradication) में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (LWE) राजीव कुमार ने विश्लेषण किया है कि कैसे 1967 के नक्षलबाड़ी विद्रोह से शुरू हुआ वामपंथ उग्रवाद (LWE) अंततः मार्च 2026 तक देश से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।

लेखक रेखांकित करते हैं कि 2009-10 के दौरान नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी (1,936 घटनाएं और 1,005 मौतें), और यह खतरा देश के एक-तिहाई हिस्से (रेड कॉरिडोर) में फैल चुका था। इस बहुआयामी चुनौती से निपटने के लिए 2015 में एक व्यापक «राष्ट्रीय नीति और एक्शन प्लान» तैयार किया गया, जिसमें «समग्र सरकार» (Whole-of-Government) के दृष्टिकोण को अपनाया गया।

2. नक्सलवाद की कार्यप्रणाली और चरम हिंसा का दौर

- राज्यसत्ता को चुनौती:** चारू मजूमदार और कानू सान्याल द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था।
- रणनीति और क्षेत्र चयन:** नक्सलियों ने घने जंगलों, दुर्गम इलाकों और कमजोर प्रशासनिक पहुंच वाले क्षेत्रों को चुना, जहां उन्होंने «जनता सरकार» और समानांतर अदालतें बनाईं।
- चरम हिंसा:** 2010 में ताड़मेटला (दंतेवाड़ा) हमले में 76 सुरक्षाकर्मियों की शहादत और झीरम घाटी हमले जैसे क्रूर कृत्यों के माध्यम से कुल 8,600 से अधिक नागरिकों की जान गई।

3. 2015 की राष्ट्रीय नीति और चार प्रमुख स्तंभ

गृह मंत्रालय की 2015 की नीति चार मुख्य स्तंभों पर आधारित थी:

- सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना:** राज्यों की पुलिस को मुख्य भूमिका में रखते हुए सुरक्षा वैक्यूम को खत्म करना और हर 5 किमी पर सुरक्षा कैंप स्थापित करना।
- विकास कार्य और संपर्क:** सड़क, रेल, दूरसंचार (मोबाइल टावर) और वित्तीय समावेशन (बैंक व पोस्ट ऑफिस) के जरिए सुदूर गांवों को जोड़ना।
- स्थानीय समुदायों के अधिकार और हकदारी:** भूमि और वन अधिकारों (Forest Rights Act) के तहत 1.8 मिलियन टाइटल डीड का वितरण।
- जन-आउटरीच और धारणा प्रबंधन:** ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और नागरिक कार्यवाई कार्यक्रमों के जरिए विश्वास बहाली।

4. सुरक्षा और विकासात्मक बुनियादी ढांचे की प्रगति

- सुरक्षा क्षमता निर्माण:** SRE और SIS योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपये जारी किए गए। लगभग 706 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए। छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर 10,000+ जवानों के साथ «ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट» (2025) चलाया गया।
- सड़क और रेल संपर्क:** PMGSY और LWE रोड प्रोजेक्ट्स के तहत हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई गईं, जिससे सड़क घनत्व में 30% और हाईवे कनेक्टिविटी में 80% सुधार हुआ।
- डिजिटल और वित्तीय समावेशन:** 9,000+ मोबाइल टावर लगाए गए (96% गांवों में कवरेज), 1,800+ बैंक शाखाएं खुलीं, तथा 259 EMRS (Eklayva Model Residential Schools) स्वीकृत किए गए।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: LWE उन्मूलन के आयाम, उपाय और परिणाम

नीचे दी गई तालिका LWE उन्मूलन के लिए अपनाई गई रणनीतियों, विकास पहलों और ऐतिहासिक परिणामों का विवरण प्रस्तुत करती है:

उन्मूलन आयाम	प्रमुख रणनीति / नीतिगत उपाय	कार्यान्वयन व पैमाना	परिणाम व प्रभाव (2010 बनाम 2025)
सुरक्षा और आधारभूत ढांचा	कोर LWE क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप स्थापना और फोर्टिफाइड थाने	833+ सुरक्षा कैंप और 660+ फोर्टिफाइड थाने निर्मित	सुरक्षा वैक्यूम समाप्त और राज्य की संप्रभुता स्थापित
सड़क और दूरसंचार संपर्क	विशेष सड़क योजनाएं और 4G/2G मोबाइल टावर स्थापना	9,000+ मोबाइल टावर और हजारों किमी सड़कें स्वीकृत	दुर्गम क्षेत्रों का डिजिटल और भौतिक एकीकरण
वित्तीय और सामाजिक विकास	बैंकिंग पहुंच, EMRS स्कूल और कौशल विकास केंद्र	1,800+ बैंक शाखाएं और 179+ EMRS स्कूल चालू	गरीबी और अलगाव की जड़ों पर प्रहार, समावेशी विकास
हिंसा में ऐतिहासिक गिरावट	चारों स्तंभों पर आधारित 'समग्र सरकार' (Whole-of-Government) दृष्टिकोण	2010 से 2025 के बीच हिंसा में 88% और मौतों में 90% कमी	मार्च 2026 तक भारत का पूर्ण रूप से नक्सल-मुक्त होना

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख आंतरिक सुरक्षा, शासन व्यवस्था और नीतिगत समन्वय के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (आंतरिक सुरक्षा — उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास का समन्वय; 'समग्र सरकार' दृष्टिकोण का क्रियान्वयन)

- **‘समग्र सरकार’ (Whole-of-Government) मॉडल:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे सुरक्षा उपायों, त्वरित विकास, स्थानीय अधिकारों और जन-आउटरीच के चार स्तंभों ने मिलकर एक जटिल आंतरिक सुरक्षा चुनौती को सफलता में बदला है?
- **सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism):** केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत समन्वय, वित्तीय सहायता (SRE/SIS) और जिला-स्तरीय निगरानी तंत्र के माध्यम से दीर्घकालिक शांति स्थापना के मॉडल को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा LWE दृष्टिकोण: नक्सलबारी से लेकर मार्च 2026 तक की यात्रा यह साबित करती है कि यदि सुरक्षा, विकास और सुशासन को एक साथ मिला दिया जाए, तो भारत के संघीय ढांचे में सबसे जटिल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक समाधान किया जा सकता है।

विषय 5: बस्तर ओलंपिक: बस्तर में शांति, समावेश और परिवर्तनकारी बदलाव का उत्प्रेरक (BAS-TAR OLYMPICS: A CATALYST FOR PEACE, INCLUSION, AND TRANSFORMATIONAL CHANGE IN BAS-TAR)

बस्तर ओलंपिक (2024-2025), संघर्ष से आत्मविश्वास, भारी जनभागीदारी (3.91 लाख+ प्रतिभागी), समावेशी 'नुवा बात' (Nuva Baat) टीम (पूर्व नक्सली और दिव्यांग एथलीट), खेल बुनियादी ढांचा, और युवा सशक्तिकरण (लेखक: सुंदरराज पी., पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज)

बस्तर ओलंपिक विजन: “बस्तर का परिवर्तन साहस, दृढ़ता और सामूहिक प्रयास की कहानी है। बस्तर ओलंपिक इस कथा में सबसे आगे है, जो यह दर्शाता है कि खेल किस प्रकार सीमाओं को पार कर सकता है और दूरियों को मिटा सकता है।” — सुंदरराज पी.

1. कार्यकारी सारांश एवं सामाजिक पुनरुत्थान

जून 2026 के 'योजना' अंक के चौथे आलेख 'बस्तर ओलंपिक: बस्तर में शांति, समावेश और परिवर्तनकारी बदलाव का उत्प्रेरक' (Bastar Olympics: A Catalyst for Peace, Inclusion, and Transformational Change in Bastar) में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने विश्लेषण किया है कि कैसे कभी वामपंथ उग्रवाद (LWE) के साये में रहने वाला बस्तर अब खेल, आशा और सकारात्मक परिवर्तन के एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन की गवाही दे रहा है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि बस्तर ओलंपिक 2025 (अपने 2024 के सफल पहले संस्करण की तर्ज पर) केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक राष्ट्र-निर्माण की दिशा में मोड़ने और भय के नैरेटिव को आत्मविश्वास में बदलने का एक अनूठा माध्यम बन गया है।

2. संघर्ष से आत्मविश्वास और भारी जनभागीदारी

- **प्रतिभा की कोई कमी नहीं:** बस्तर के युवाओं को दशकों तक अवसरों और मंचों से वंचित रखा गया, लेकिन उनमें प्रतिभा, साहस और क्षमता की कभी कोई कमी नहीं थी। बस्तर ओलंपिक ने इस खाई को पाटने का काम किया है।
- **रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी:** 2024 में लगभग 1.65 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जो 2025 में बढ़कर 3.91 लाख से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंच गया। इसमें महिलाओं की भारी संख्या लैंगिक समावेशन और सशक्तिकरण का प्रमाण है।

3. समावेशी दृष्टिकोण: 'नुवा बात' (Nuva Baat) टीम

- **समावेशी पहल:** बस्तर ओलंपिक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समावेशिता है। इसमें सुदूर गांवों के आदिवासियों के साथ-साथ हिंसा छोड़ने वाले पूर्व नक्सली, नक्सली हिंसा के पीड़ित, और विशेष रूप से सक्षम (divyang) एथलीटों को भी शामिल किया गया।
- **'नुवा बात' (नया रास्ता):** स्थानीय बोली में 'नुवा बात' नाम से एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें मुख्यधारा में लौटे पूर्व कैडर और पीड़ित एक नई पहचान के साथ एथलीट के रूप में शामिल हुए, जिससे यह संदेश गया कि विकास और गरिमा पर सबका अधिकार है।

4. पेशेवर आयोजन और खेल बुनियादी ढांचा

- **बहु-स्तरीय प्रतियोगिताएं:** ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर आयोजित इन खेलों में 32 विकास ब्लॉकों में 60 से अधिक खेल मैदान तैयार किए गए।
- **पारंपरिक और आधुनिक खेल:** एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल जैसे आधुनिक खेलों के साथ पारंपरिक खेलों को भी जोड़ा गया। राष्ट्रीय स्तर के रेफरी और मानकीकृत बुनियादी ढांचे ने इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: बस्तर ओलंपिक आयाम और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका बस्तर ओलंपिक के प्रमुख घटकों, पैमाने और सामाजिक प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

ओलंपिक आयाम	प्रमुख रणनीति / पहल	परिचालन पैमाना व मैट्रिक्स	सामाजिक व मानसिक प्रभाव
जनभागीदारी और पैमाना	युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना	1.65 लाख (2024) से बढ़कर 3.91 लाख+ प्रतिभागी (2025)	युवाओं की सोच में बदलाव; हिंसा की जगह खेल के मैदानों का चयन
समावेशी 'नुवा बात' टीम	पूर्व नक्सलियों, पीड़ितों और दिव्यांगों को खेल मंच देना	विशेष 'नुवा बात' टीम का गठन और मुख्यधारा में एकीकरण	सामाजिक दूरियों को पाटना और समानता का संदेश देना
खेल बुनियादी ढांचा	ब्लॉक और जिला स्तर पर मानकीकृत खेल सुविधाएं	60+ खेल मैदान, प्रशिक्षित रेफरी और पेशेवर प्रबंधन	खेल संस्कृति का विकास और राज्य/राष्ट्रीय स्तर की तैयारी
चरमपंथ का कमजोर होना	सार्थक व्यस्तता और सामुदायिक जुड़ाव	सांसदों, समुदायों और परिवारों की व्यापक सहभागिता	कट्टरपंथ और अलगाववाद के आधार को कमजोर करना

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक समावेश और सॉफ्ट पावर के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (आंतरिक सुरक्षा — उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास बहाली, युवाओं का मुख्यधारा में एकीकरण और खेल आधारित शांति निर्माण)

- खेल और शांति निर्माण (Sports as a Catalyst for Peace):** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे बस्तर ओलंपिक जैसी पहलें सुरक्षा अभियानों के पूरक के रूप में काम करते हुए युवाओं को कट्टरपंथ से बचाती हैं और उनमें आत्मविश्वास जगाती हैं?
- सामाजिक समावेश ('नुवा बात' मॉडल):** पूर्व नक्सलियों और पीड़ितों को एक साथ खेल मंच पर लाकर सामाजिक समरसता स्थापित करने के अनूठे मॉडल को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा बस्तर ओलंपिक दृष्टिकोण: बस्तर की पहचान को संघर्ष क्षेत्र से निकालकर प्रतिभा और आशा के उद्गम स्थल के रूप में पुनर्परिभाषित करना यह साबित करता है कि खेल विभाजन को मिटाने और स्थायी शांति लाने का सबसे प्रभावी साधन है?

विषय 6: शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की भूमिका (EMPOWERING THROUGH EDUCATION: ROLE OF EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOLS)

वामपंथ उग्रवाद (LWE) क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व, EMRS (एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल) योजना का विस्तार (259+ स्वीकृत स्कूल, 50,000+ छात्र), आधुनिक बुनियादी ढांचा व डिजिटल प्रयोगशालाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और जनजातीय युवाओं में बढ़ती आकांक्षाएं (लेखक: अजीत कुमार श्रीवास्तव, पूर्व कमिश्नर, NESTS)

शिक्षा सशक्तिकरण विजन: “आकांक्षाओं का पोषण करके, आत्मविश्वास का निर्माण करके और समुदायों को मुख्यधारा में एकीकृत करके, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल उन आधारों को कमजोर करते हैं जिन पर उग्रवाद पनपता है।” — अजीत कुमार श्रीवास्तव

1. कार्यकारी सारांश एवं नक्सलवाद विरोधी संघर्ष में शिक्षा की भूमिका

जून 2026 के «योजना» अंक के पांचवें आलेख «शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की भूमिका» (Empowering through Education: Role of Eklavya Model Residential Schools) में राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी (NESTS) के पूर्व कमिश्नर अजीत कुमार श्रीवास्तव ने विश्लेषण किया है कि कैसे वामपंथ उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा ने उग्रवाद के सामाजिक-आर्थिक आधार को समाप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि ऐतिहासिक रूप से नक्सली समूहों ने जनजातीय क्षेत्रों की गरीबी, अलगाव और शिक्षा की कमी का फायदा उठाकर कम उम्र के बच्चों को गुमराह किया और हिंसा के रास्ते पर धकेला। यह स्पष्ट हो गया कि केवल सुरक्षा अभियानों से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता; इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास का प्रसार आवश्यक था।

2. EMRS (एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल) का विकास और आवासीय मॉडल

- नीतिगत बदलाव (2018):** 1999 में शुरू हुई आदिवासी आवासीय विद्यालय योजना को 2018 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसके तहत कक्षा 12 तक पूरी तरह से आवासीय, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की गई।
- उग्रवाद विरोधी प्रभाव:** EMRS छात्रों को उनके अपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में सुरक्षा और अवसर प्रदान करते हैं। यह आवासीय मॉडल बच्चों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उग्रवादी संगठनों के प्रभाव से दूर रखता है।

3. आधुनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल सशक्तिकरण और गुणवत्ता

- आधुनिक सुविधाएं:** इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ताकि जनजातीय छात्र शहरी क्षेत्रों के छात्रों के साथ मुकाबला कर सकें।
- CBSE संबद्धता और शिक्षक प्रशिक्षण:** सभी EMRS स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया गया है, और अखिल भारतीय परीक्षाओं के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जो छात्रों के संरक्षक (mentors) की भूमिका निभाते हैं।

4. उत्कृष्टता केंद्र और बढ़ती सामुदायिक साख

- IIT/NEET कोचिंग:** मेधावी छात्रों के लिए विशेष 'सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' बनाए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देते हैं।
- बढ़ती मांग:** जनजातीय परिवारों में शिक्षा के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप EMRS में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: EMRS शिक्षा आयाम, पैमाने और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका EMRS शिक्षा के प्रमुख घटकों, बुनियादी ढांचे और सामाजिक प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

शिक्षा आयाम	मुख्य रणनीति / नीतिगत पहल	संचालन पैमाना व मैट्रिक्स	सामाजिक व सुरक्षा प्रभाव
नीतिगत विस्तार	LWE क्षेत्रों में EMRS विद्यालयों की स्थापना व आवासीय सुविधा	259 स्वीकृत स्कूल (178+ कार्यरत); 50,000+ छात्र नामांकित	उग्रवादी समूहों के लिए युवा भर्ती की आपूर्ति श्रृंखला बाधित
आधुनिक बुनियादी ढांचा	स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और हाई-स्पीड इंटरनेट	सभी परिसरों में डिजिटल लर्निंग टूल्स और विज्ञान प्रयोगशालाएं	ग्रामीण और शहरी शिक्षा की खाई को पाटना
गुणवत्ता और शिक्षण	CBSE संबद्धता और अखिल भारतीय स्तर पर योग्य शिक्षकों की भर्ती	मानकीकृत पाठ्यक्रम और विशेष परामर्श (counseling)	छात्रों में तार्किक सोच, आत्मविश्वास और मुख्यधारा की योग्यता
उत्कृष्टता और आकांक्षा	IIT/NEET के लिए विशेष 'सेटर्स ऑफ एक्सीलेंस' कोचिंग	विशेषीकृत प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन पहल	युवाओं में उच्च शिक्षा के प्रति महत्वाकांक्षा और प्रेरणा

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख शिक्षा नीति, मानव संसाधन और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & III (सामाजिक क्षेत्र — शिक्षा और जनजातीय कल्याण से संबंधित मुद्दे; आंतरिक सुरक्षा — उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानव पूंजी विकास और संघर्ष समाधान)

- **शिक्षा और उग्रवाद उन्मूलन:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा देकर उन्हें उग्रवाद के प्रभाव से बचाते हैं और राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हैं?
- **मानव पूंजी और समावेशी विकास:** दूरदराज के क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे (स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब) के प्रसार के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने के प्रयासों को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा EMRS दृष्टिकोण: आकांक्षाओं का पोषण करके, आत्मविश्वास का निर्माण करके और समुदायों को मुख्यधारा में एकीकृत करके, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल उन आधारों को कमजोर करते हैं जिन पर उग्रवाद पनपता है।

विषय 7: नक्सल-मुक्त भारत का दूरसंचार प्रक्षेपवक्र (THE TELECOM TRAJECTORY OF A NAXAL-FREE INDIA)

LWE क्षेत्रों में दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल भारत निधि (DBN), LWE चरण-I और चरण-II परियोजनाएं, 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट, सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण, तथा अलग-अलग से एकीकरण का सफर (लेखक: रितेश कावड़िया, उप महानिदेशक - डिजिटल भारत निधि, दूरसंचार विभाग)

दूरसंचार कनेक्टिविटी विजन: “इन क्षेत्रों का प्रक्षेपवक्र एक गहरे बदलाव को दर्शाता है—बल से जुड़ाव की ओर, बहिष्करण से समावेश की ओर, और उग्रवाद से एकीकरण की ओर। माओवादी सिद्धांत ‘बंदूक की नली से सत्ता निकलती है’ को इस वास्तविकता ने बदल दिया है कि ‘अब विकास कनेक्टिविटी के नेटवर्क से बढ़ता है।’” — रितेश कावड़िया

1. कार्यकारी सारांश एवं संपर्क की शक्ति

जून 2026 के «योजना» अंक के छठे आलेख «नक्सल-मुक्त भारत का दूरसंचार प्रक्षेपवक्र» (The Telecom Trajectory of a Naxal-Free India) में दूरसंचार विभाग (सञ्चार मंत्रालय) के डिजिटल भारत निधि के उप महानिदेशक रितेश कावड़िया ने विश्लेषण किया है कि कैसे सुदूर और वामपंथ उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क ने राज्य की उपस्थिति, कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि दशकों तक LWE-प्रभावित क्षेत्र डिजिटल और भौतिक रूप से कटे हुए थे, जिस खालीपन का फायदा उग्रवादियों ने उठाया। दूरसंचार टावर केवल सिग्नल नहीं भेजते; वे शासन, अवसर और विश्वास का संचार करते हैं। आज डिजिटल भारत के युग में मोबाइल नेटवर्क कल्याणकारी योजनाओं (PM-KISAN, जन धन, UPI, आयुष्मान भारत) की रीढ़ बन चुके हैं।

2. डिजिटल भारत निधि (DBN) और लक्षित परियोजनाएं

- **डिजिटल भारत निधि (पूर्व में USOF):** वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में किफायती और न्यायसंगत दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करना।
- **LWE चरण-I परियोजना (2014):** मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद 106 LWE-प्रभावित जिलों में 2G मोबाइल सेवाओं के लिए 2,340 मोबाइल टावर लगाए गए, जिन्हें बाद में 4G में अपग्रेड किया गया।
- **LWE चरण-II परियोजना (2018):** व्यवहार्यता अंतर फंडिंग (VGF) मॉडल का उपयोग करके 1,216 अतिरिक्त मोबाइल टावर स्थापित किए गए।

3. 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट और पर्यावरण संरक्षण

- **अन्य DBN पहलें:** LWE योजनाओं के अलावा, 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट और आकांक्षी जिला (Aspirational Districts) योजनाओं के तहत 5,863 अतिरिक्त मोबाइल टावर चालू किए गए। आज DBN टावर 30 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवा दे रहे हैं।
- **पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा:** दुर्गम और वनीय क्षेत्रों में स्थापित अधिकांश टावरों में सौर ऊर्जा (solar power) जैसे दोहरे बिजली स्रोतों का उपयोग किया गया है। साथ ही, वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पर्यावरण मानदंडों का पूर्ण पालन किया गया है।

4. चुनौतियां और धरातलीय परिवर्तन

- **सुरक्षा और भूभाग की बाधाएं:** उग्रवादियों द्वारा टावरों को जलाए जाने, सड़क व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव और सुरक्षा जोखिमों के बावजूद मंत्रिमंडलीय सचिव के नेतृत्व में निरंतर समीक्षा और PMIS डैशबोर्ड के जरिए समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।
- **सूकमा और मलकानगिरी का उदाहरण:** छत्तीसगढ़ के सूकमा और ओडिशा

दूरसंचार आयाम	प्रमुख योजना / पहल	परिचालन पैमाना व मेट्रिक्स	सामाजिक व प्रशासनिक प्रभाव
LWE चरण-I और II	गृह मंत्रालय के चिन्हित क्षेत्रों में 2G/4G मोबाइल टावर स्थापना	3,500+ टावर (चरण-I में 2,290 और चरण-II में 1,216)	सुदूर अंचल में पहली बार डिजिटल कनेक्टिविटी की नींव पड़ी
4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट	स्वदेशी 4G स्टैक के माध्यम से दूरदराज के गांवों को जोड़ना	DBN परियोजनाओं के तहत 5,863 अतिरिक्त टावर स्थापित	देशव्यापी डिजिटल समावेशन और 'आत्मनिर्भर भारत' को बल
सतत ऊर्जा व पर्यावरण	सौर ऊर्जा बैंकअप और वन कानूनों (FRA/FCA) का अनुपालन	पर्यावरण अनुकूल टावर स्थापना और CAMPA के तहत वृक्षारोपण	पारिस्थितिक संतुलन के साथ बुनियादी ढांचे का विकास
शासन और सुरक्षा तालमेल	डैशबोर्ड आधारित निगरानी और उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा	30 लाख+ उपयोगकर्ता लाभान्वित (10 लाख+ LWE क्षेत्रों में)	सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल दक्षता और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख डिजिटल बुनियादी ढांचे, ई-गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (आंतरिक सुरक्षा — उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन, ई-गवर्नेंस के माध्यम से राज्य की उपस्थिति और बुनियादी ढांचे का विकास)

- **डिजिटल कनेक्टिविटी और आंतरिक सुरक्षा:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे LWE क्षेत्रों में मोबाइल टावर और फाइबर नेटवर्क स्थापित करने से न केवल सुरक्षा बलों की सूचना प्रणाली मजबूत हुई है, बल्कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और ई-गवर्नेंस का विस्तार भी हुआ है
- **अलगाव से एकीकरण का सफर:** दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रसार के माध्यम से उग्रवाद के सामाजिक आधार को कमजोर करने और नागरिकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने के मॉडल को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा दूरसंचार दृष्टिकोण: इन क्षेत्रों का प्रक्षेपवक्र एक गहरे बदलाव को दर्शाता है—बल से जुड़ाव की ओर, बहिष्करण से समावेश की ओर, और उग्रवाद से एकीकरण की ओर।

विषय 8: पांच दशकों के उग्रवाद का अंत करने वाला दृष्टिकोण (THE APPROACH THAT ENDED A FIVE-DECADE INSURGENCY)

वामपंथ उग्रवाद (LWE) का अंत, 31 मार्च 2026 की घोषणा, MHA (गृह मंत्रालय) का रणनीतिक तंत्र, SAMADHAN सिद्धांत, खुफिया क्रांति (HUMINT और तकनीकी सर्विलांस), और बस्तर व अबूझमाड़ के गढ़ों का पतन (लेखक: कंचन लक्ष्मण, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक)

राष्ट्रीय संकल्प दृष्टि: “31 मार्च 2026 की घोषणा कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक निरंतर, प्रणाली-संचालित परिवर्तन का परिणाम था, जहां खुफिया तंत्र ने नेतृत्व किया, सुरक्षा बल तालमेल के साथ आगे बढ़े, और राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत बनी रही।” — कंचन लक्ष्मण

के मलकानगिरी जैसे जिलों में जहां पहले कोई सिग्रल नहीं था, अब मोबाइल नेटवर्क ने सुरक्षा बलों के समन्वय और स्थानीय नागरिकों के लिए बाजार, शिक्षा व बैंकिंग के द्वार खोल दिए हैं।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: दूरसंचार आयाम, पहल और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका दूरसंचार पहलों, उनके पैमाने और LWE क्षेत्रों में पड़े सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

1. कार्यकारी सारांश एवं ऐतिहासिक बदलाव

जून 2026 के 'योजना' अंक के सातवें आलेख 'पांच दशकों के उग्रवाद का अंत करने वाला दृष्टिकोण' (The Approach that Ended a Five-Decade Insurgency) में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक कंचन लक्ष्मण ने विश्लेषण किया है कि कैसे 31 मार्च 2026 को भारत को नक्सल-मुक्त घोषित किए जाने का ऐतिहासिक क्षण दशकों की प्रतिक्रियावादी आतंकवाद-विरोधी नीतियों से हटकर एक सुनियोजित रणनीतिक वास्तुकला (strategic architecture) का परिणाम है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि 2010 के दंतेवाड़ा हमले (76 जवानों की शहादत) से लेकर 2026 तक के सफर में जो बदलाव आया, वह केवल अधिक हथियारों का नहीं था, बल्कि रणनीतिक सोच, राजनीतिक इच्छाशक्ति, खुफिया सटीक और संघीय समन्वय (federal coordination) का एक अनूठा संगम था जिसने दुनिया के सबसे लंबे Maoist विद्रोह का अंत किया।

2. MHA (गृह मंत्रालय) का रणनीतिक तंत्र और SAMADHAN सिद्धांत

- **गृह मंत्रालय की केंद्रीय भूमिका:** 2015 की राष्ट्रीय नीति और एक्शन प्लान के तहत MHA ने सुरक्षा अभियानों, विकास वितरण और अंतर-राज्यीय समन्वय का नेतृत्व किया।
- **SAMADHAN सिद्धांत:** स्मार्ट लीडरशिप, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी, डैशबोर्ड-आधारित KPI, प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रत्येक थिएटर के लिए एक्शन प्लान, और वित्तपोषण तक पहुंच को रोकना।

3. खुफिया क्रांति: प्रतिक्रियावादी से भविष्य-दर्शी दृष्टिकोण

- **HUMINT और तकनीकी सर्विलांस:** आत्मसमर्पित कैडरों के पुनर्वास से मजबूत हुए मानव खुफिया नेटवर्क (HUMINT) ने PLGA संरचनाओं और आंदोलनों का सटीक डेटा दिया।
- **सटीक प्रहार:** ड्रोन, मोबाइल सिग्रल इंटरसेप्शन और उपग्रह इमेजरी के संयोजन ने उग्रवादियों को पहले ही बेअसर करने में मदद की, जिससे शीर्ष नेतृत्व का पूर्ण पतन हुआ।

4. बस्तर और अबूझमाड़ के गढ़ों का भेदन

- बस्तर में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs): जंगलों के भीतर स्थायी सुरक्षा उपस्थिति दर्ज करके नक्सलियों की आपूर्ति लाइनों को काटा गया और राज्य की संप्रभुता बहाल की गई।
- अबूझमाड़ का भेदन: 'अज्ञात पहाड़ियों' के रूप में कुख्यात अबूझमाड़ में

रणनीतिक आयाम	पूर्ववर्ती प्रतिक्रियावादी नीति	परिवर्तित दृष्टिकोण (2014-2026)	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव
रणनीतिक वास्तुकला	खंडित प्रतिक्रियाएं और समय-बद्ध लक्ष्यों का अभाव	SAMADHAN सिद्धांत और MHA का केंद्रीय नेतृत्व व स्पष्ट समय-सीमा	सैन्य और प्रशासनिक कार्रवाइयों में अभूतपूर्व तालमेल
खुफिया वास्तुकला	घटना के बाद प्रतिक्रिया (Reactive operations)	आत्मसमर्पित कैडरों के नेटवर्क और आधुनिक तकनीक (ड्रोन/सिग्नल) का उपयोग	नक्सली गतिविधियों की पूर्व-सूचना और नेतृत्व का सटीक खात्मा
दुर्गम गढ़ों पर प्रहार	अबूझमाड़ और सुकमा के जंगलों में सीमित पहुंच	हेलिकॉप्टर लॉजिस्टिक्स, FOBs और सड़क निर्माण के जरिए स्थायी नियंत्रण	उग्रवादियों की सुरक्षित पनाहगाहों का हमेशा के लिए खात्मा
संघर्ष समाधान	केवल सैन्य बल पर अत्यधिक निर्भरता	सुरक्षा, विकास, मानवीय पुनर्वास और नागरिक आउटरीच का त्रि-आयामी मॉडल	संविधान की पुनर्स्थापना और स्थायी शांति की प्राप्ति

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख आंतरिक सुरक्षा, रणनीतिक प्रबंधन और उग्रवाद उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (आंतरिक सुरक्षा — उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रणनीतिक वास्तुकला, खुफिया सुधार और संवैधानिक आदेश की पुनर्स्थापना)

- उग्रवाद उन्मूलन की रणनीतिक वास्तुकला:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे MHA के केंद्रीय नेतृत्व, SAMADHAN सिद्धांत और खुफिया-आधारित सटीक ऑपरेशनों ने पांच दशकों पुराने विद्रोह को समाप्त किया?
- संवैधानिक पुनर्स्थापना:** उग्रवाद-मुक्त भारत की घोषणा को केवल सुरक्षा सफलता नहीं, बल्कि देश के हर कोने में संविधान के शासन और नागरिक अधिकारों की पूर्ण बहाली के रूप में रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा रणनीतिक दृष्टिकोण: नक्सल-मुक्त भारत केवल एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं है। यह एक संवैधानिक पुनर्स्थापना है, जो भारतीय राज्य की अपने क्षेत्र के प्रत्येक इंच पर और वहां के नागरिकों को उनके अधिकारों की पूर्ण वापसी को सुनिश्चित करती है।

विषय 9: LWE-प्रभावित क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट: अलगाव से एकीकरण तक (INDIA POST IN LWE-AFFECTED REGIONS: FROM ISOLATION TO INTEGRATION)

वामपंथ उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का विस्तार, ब्रांच ऑफिस (BOs) की स्थापना (1,789 और 3,114 चरण), इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), और ग्रामीण डाक सेवकों की भूमिका (लेखक: दुष्यंत मुद्गल, उप महानिदेशक - स्थापना और योजना, भारतीय डाक विभाग)

इंडिया पोस्ट विजन: “डाक नेटवर्क ने, अपनी गहरी स्थानीय जड़ों और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से मानवीय इंटरफेस के साथ, उन समुदायों में विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण किया है जो कभी पहुंच से दूर थे। इंडिया पोस्ट केवल पत्र नहीं पहुंचा रहा; यह स्थिरता, अवसर और एकीकरण पहुंचा रहा है।” — दुष्यंत मुद्गल

हेलिकॉप्टरों द्वारा रसद आपूर्ति, ड्रोन टोह और निरंतर खुफिया ऑपरेशनों के माध्यम से नक्सलियों के सर्वोच्च अभयारण्य को ध्वस्त किया गया।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: उग्रवाद अंत के रणनीतिक आयाम और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका पांच दशकों के उग्रवाद के अंत में काम करने वाली रणनीतिक प्रणालियों और उनके प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

1. कार्यकारी सारांश एवं इंडिया पोस्ट की भूमिका

जून 2026 के 'योजना' अंक के आलेख 'LWE-प्रभावित क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट: अलगाव से एकीकरण तक' (India Post in LWE-Affected Regions: From Isolation to Integration) में भारतीय डाक विभाग के उप महानिदेशक (स्थापना और योजना) दुष्यंत मुद्गल ने विश्लेषण किया है कि कैसे भारतीय डाक (India Post) ने वामपंथ उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में सुशासन और आवश्यक सेवाओं के विस्तार में शांत लेकिन परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि अपने सुदृढ़ जमीनी नेटवर्क और ग्रामीण डाक सेवकों (Gramin Dak Sevaks) के माध्यम से, डाक विभाग ने उन सुदूर क्षेत्रों में औपचारिक संचार और वित्तीय प्रणालियों को पहुंचाया है जो पहले पूरी तरह कटे हुए थे।

2. ब्रांच ऑफिस (BOs) का व्यवस्थित विस्तार

- प्रथम चरण (2016-17):** LWE क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की नींव रखते हुए 1,789 नई ब्रांच शाखाएं (Branch Offices) स्थापित की गईं
- द्वितीय चरण (2021-22):** संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंच को और गहरा करने के लिए 3,114 अतिरिक्त ब्रांच ऑफिस खोले गए
- समेकन (2024-25):** देश के नक्सल-मुक्त होने की दिशा में प्रगति के अनुरूप 294 नए ब्रांच ऑफिस खोले गए, जो सुदृढ़ीकरण और विकास के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं।

3. वित्तीय समावेशन और नागरिक-केंद्रित सेवाएं

- बहुआयामी सेवाएं:** ये ब्रांच ऑफिस डाक वितरण, बचत और बैंकिंग सुविधाओं (इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), बीमा और आधार-सक्षम सेवाओं के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं?
- अलगाव को कम करना:** जिन क्षेत्रों में पारंपरिक बैंकिंग अवसरचना नहीं पहुंच पाई, वहां इंडिया पोस्ट ने सरकार और जनता के बीच एक भरोसेमंद और सुलभ माध्यम के रूप में कार्य किया है।

4. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मेट्रिक्स: इंडिया पोस्ट आयाम और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका LWE क्षेत्रों में डाक नेटवर्क के विस्तार और उसके सामाजिक प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

डाक विस्तार आयाम	मुख्य नीतिगत पहल	कार्यान्वयन पैमाना व मेट्रिक्स	सामाजिक व प्रशासनिक प्रभाव
ब्रांच ऑफिस स्थापना	LWE क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डाक शाखाओं का विस्तार	1,789 (2016-17) और 3,114 (2021-22) नई शाखाएं स्थापित	सुदूर और संवेदनशील क्षेत्रों में औपचारिक संचार की बहाली
वित्तीय समावेशन	IPPB और DBT के माध्यम से बैंकिंग व कल्याणकारी लाभ	बचत, बीमा और आधार-सक्षम वित्तीय सेवाएं सुलभ	पारंपरिक बैंकिंग के अभाव को दूर करना और आर्थिक सुरक्षा
स्थानीय विश्वास	ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के जरिए मानवीय इंटरफेस	दूरदराज के गांवों में सीधा संपर्क और संवाद	समुदायों में सरकार के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण
राष्ट्रीय एकीकरण	अलगाव और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यधारा से जुड़ाव	नक्सल-मुक्त भारत के विजन के अनुरूप डाक पदचिह्न का प्रसार	स्थिरता, अवसर और राष्ट्रीय एकीकरण की प्राप्ति

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख लोक सेवा वितरण, वित्तीय समावेशन और आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & III (शासन व्यवस्था — सरकारी नीतियों और सेवा वितरण का क्रियान्वयन; आंतरिक सुरक्षा — उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच और विश्वास बहाली)

- डाक नेटवर्क और सुशासन:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे भारतीय डाक ने अपने सुदूर नेटवर्क (Branch Offices) और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से सुदूर LWE क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी योजनाओं (DBT) का विस्तार किया है
- अलगाव से एकीकरण:** बुनियादी प्रशासनिक और वित्तीय सेवाओं की पहुंच के माध्यम से जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करने और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के मॉडल को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा इंडिया पोस्ट दृष्टिकोण: इंडिया पोस्ट केवल पत्र और पार्सल नहीं पहुंचा रहा है; यह स्थिरता, अवसर और एकीकरण पहुंचा रहा है।

विषय 10: पूर्व LWE क्षेत्रों में लोकतंत्र को सुरक्षित करना: क्षेत्र, विश्वास और संक्रमण (SECURING DEMOCRACY IN FORMERLY LWE REGIONS: TERRITORY, TRUST, TRANSITION)

माओवादी «जनता सरकार» का पतन, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, क्षेत्रीय नियंत्रण व अंतरिक्ष विजय, विश्वास बहाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं का विस्तार (लेखक: अभिराम चैदयालपाटिल, वरिष्ठ पत्रकार एवं कार्यकारी निदेशक, रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी)

लोकतंत्र सुरक्षा दृष्टि: “नक्सली क्षेत्रों में ‘जनता सरकार’ जैसी एक अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक सतर्कता संरचना थी। इस कानूनविहीन ढांचे को तोड़ना और भारतीय संविधान को देश के एकमात्र कानून के रूप में स्थापित करना नक्सलवाद के खिलाफ पहली और बहुत जरूरी जीत है।” — अभिराम चैदयालपाटिल

1. कार्यकारी सारांश एवं लोकतंत्र की पुनर्स्थापना

जून 2026 के «योजना» अंक के आठवें आलेख «पूर्व LWE क्षेत्रों में लोकतंत्र को सुरक्षित करना: क्षेत्र, विश्वास और संक्रमण» (Securing Democracy in Formerly LWE Regions: Territory, Trust, Transition) में वरिष्ठ पत्रकार और रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के कार्यकारी निदेशक अभिराम चैदयालपाटिल ने विश्लेषण किया है कि कैसे नक्सल-मुक्त घोषित होने के बाद अब इन सुदूर क्षेत्रों में जमीनी लोकतंत्र (grassroots democracy) की स्थापना और उसे गहरा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब डिजिटल लोकतंत्र सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, जहां देश भर से आए कंटेंट क्रिएटर्स और पर्यटक इंद्रावती नदी पर राफ्टिंग कर रहे हैं और मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों से मिल रहे हैं। यह सामान्य स्थिति कुछ वर्ष पहले अकल्पनीय थी, जो उग्रवाद पर लोकतंत्र की पूर्ण विजय को दर्शाती है।

2. «जनता सरकार» का पतन और संविधान की सर्वोच्चता

- असंवैधानिक ढांचे का अंत:** नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों ने «जनता सरकार» नामक एक अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक समानांतर व्यवस्था खड़ी की थी। इस कानूनविहीन ढांचे का खात्मा कर भारतीय संविधान को वहां एकमात्र कानून के रूप में स्थापित करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
- प्रादेशिक और स्थानिक नियंत्रण:** केंद्रीय गृह मंत्री अमित Shah के नेतृत्व और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण सुरक्षा बलों ने उन क्षेत्रों पर पूर्ण प्रादेशिक नियंत्रण हासिल कर लिया है जो कभी माओवादियों के «मुक्त क्षेत्र» कहे जाते थे।

3. विश्वास बहाली, विकास और डेटा संकेतक

- दुष्क्र का टूटना:** नक्सलियों ने हमेशा विकास की कमी का बहाना बनाकर खुद ही विकास कार्यों को रोका था। वर्तमान सरकार ने सुरक्षा कैंपों के माध्यम से इस दुष्क्र को तोड़ा है।
- विकास के आंकड़े:** 2024 के बाद LWE क्षेत्रों में सड़क की लंबाई में 25% की वृद्धि हुई है, 96% से अधिक गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है, और बैंक शाखाओं की संख्या 3,320 (2014) से बढ़कर 5,124 हो गई है। साथ ही 6,000 नए डाकघर खोले गए हैं।

4. सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण

- स्थानीय भागीदारी: सुरक्षा बलों में स्थानीय आदिवासियों की भर्ती, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों, तथा EMRS (एकलव्य स्कूलों) की संख्या में चार गुना वृद्धि ने स्थानीय लोगों में विश्वास और आकांक्षाओं को जन्म दिया है।

संक्रमण आयाम	पूर्ववर्ती संघर्ष व अलगाव की स्थिति	वर्तमान लोकतांत्रिक संक्रमण (2014-2026)	लोकतांत्रिक व सामाजिक प्रभाव
संविधान बनाम जनता सरकार	माओवादियों की असंवैधानिक 'जनता सरकार' और कानूनविहीन व्यवस्था	इस समानांतर ढांचे का पूर्ण विध्वंस और संविधान की सर्वोच्चता	कानून के शासन की स्थापना और सुरक्षित लोकतांत्रिक स्पेस
क्षेत्रीय नियंत्रण और कैप	दूरदराज के इलाकों में राज्य की अनुपस्थिति और सुरक्षा वैक्यूम	800+ सुरक्षा कैपों की स्थापना (400+ वर्ष 2019 के बाद निर्मित)	क्षेत्रीय प्रभुत्व और नागरिकों के लिए सुरक्षा की गारंटी
विकास और बुनियादी ढांचा	विकास कार्यों का विरोध और संपर्कों का पूर्ण अभाव	सड़क लंबाई में 25% वृद्धि, 96% गांवों में मोबाइल और 5,124 बैंक शाखाएं	अलगाव की समाप्ति और प्रशासनिक पहुंच का विस्तार
विश्वास और आकांक्षा	तीव्र अलगाव, भय और राज्य के प्रति अविश्वास	बस्तर ओलंपिक, स्थानीय भर्ती और EMRS स्कूलों का चार गुना विस्तार	सामुदायिक गौरव, मुख्यधारा से जुड़ाव और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख आंतरिक सुरक्षा, जमीनी लोकतंत्र और शासन सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & III (शासन व्यवस्था — लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना और संस्थागत विस्तार; आंतरिक सुरक्षा — उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संवैधानिक आदेश और विश्वास की बहाली)

- 'जनता सरकार' का पतन और संवैधानिक सर्वोच्चता: यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे माओवादियों के असंवैधानिक समानांतर ढांचे को समाप्त कर भारतीय संविधान को एकमात्र कानून के रूप में स्थापित किया गया है, जो लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है?
- क्षेत्र, विश्वास और संक्रमण मॉडल: सुरक्षा कैपों की स्थापना, बुनियादी विकास (सड़कें, बैंक, दूरसंचार) और सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से पूर्व LWE क्षेत्रों में लोकतंत्र को सुरक्षित करने के मॉडल को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा लोकतंत्र सुरक्षा दृष्टिकोण: नक्सली क्षेत्रों में 'जनता सरकार' जैसी एक अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक सत्कर्ता संरचना थी। इस कानूनविहीन ढांचे को तोड़ना और भारतीय संविधान को देश के एकमात्र कानून के रूप में स्थापित करना नक्सलवाद के खिलाफ पहली और बहुत जरूरी जीत है।

विषय 11: बस्तर पंडम: सांस्कृतिक मुखरता और नक्सल-मुक्त प्रक्षेपवक्र का समेकन (BASTAR PANDUM: CULTURAL ASSERTION AND THE CONSOLIDATION OF A NAXAL-FREE TRAJECTORY)

बस्तर पंडम 2026 उत्सव, जनजातीय कला और संस्कृति, 54,000+ कलाकारों की भारी भागीदारी, 1,885 ग्राम पंचायतों का जुड़ाव, विकास और सुशासन की पहल, और राष्ट्रपति व गृह मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: लोकतांत्रिक संक्रमण आयाम और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका पूर्व LWE क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संक्रमण, सुरक्षा और विकास के आयामों का विवरण प्रस्तुत करती है:

बस्तर पंडम दृष्टि: “जब किसान बीज बोते हैं, तो वह पंडम है; जब आम पकते हैं, तो वह पंडम है... समापन समारोह के दौरान उजागर की गई 55,000 से अधिक जनजातीय व्यक्तियों की भागीदारी केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के भय से दूर सामूहिक आत्मविश्वास की ओर बढ़ने का प्रमाण है।”

1. कार्यकारी सारांश एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान

जून 2026 के 'योजना' अंक के नौवें आलेख 'बस्तर पंडम: सांस्कृतिक मुखरता और नक्सल-मुक्त प्रक्षेपवक्र का समेकन' (Bastar Pandum: Cultural Assertion and the Consolidation of a Naxal-Free Trajectory) में बस्तर में सांस्कृतिक पुनरुत्थान और उत्सव के माध्यम से विश्वास बहाली की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि नक्सल-मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में केवल सुरक्षा अभियान ही पर्याप्त नहीं थे, बल्कि वहां की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला और लोक परंपराओं का सम्मान और पुनरुद्धार भी उतना ही आवश्यक था। 'बस्तर पंडम' इसी सांस्कृतिक मुखरता और बस्तर के लोगों के आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है।

2. जीवन और पहचान से जुड़ा बस्तर पंडम उत्सव

- पंडम की मूल भावना:** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जगदलपुर में 7 फरवरी 2026 को उद्घाटित इस उत्सव की जड़ें बस्तर के दैनिक जीवन, ऋतुओं और प्रकृति के साथ तालमेल में निहित हैं।
- विशाल जनभागीदारी:** 5 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक चले इस संस्करण में बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों (सुकमा, बीजापुर, दंतवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर) के 32 विकास ब्लॉकों और 1,885 ग्राम पंचायतों से 54,745 से अधिक व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।

3. सांस्कृतिक विधाओं का विस्तार और राष्ट्रीय नेतृत्व

- 12 प्रमुख श्रेणियां:** इस आयोजन में जनजातीय नृत्य, संगीत, नाटक, पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, हस्तशिल्प, चित्रकला, व्यंजन, क्षेत्रीय साहित्य और वन-आधारित औषधीय ज्ञान सहित 12 विधाओं को शामिल किया गया।

- राष्ट्रीय हस्तियों की उपस्थिति: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 फरवरी 2026 को जगदलपुर में समापन समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने बस्तर की पहचान को 'बारूद और बारूदी सुरंगों' के बजाय उसकी महान संस्कृति से जोड़ने पर बल दिया।

4. विकासत्मक पहलें और सुशासन का प्रसार

- स्कूलों और बुनियादी ढांचे का विकास: लगभग 40 वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को दोबारा खोलना, सड़क व मोबाइल टावर कनेक्टिविटी का विस्तार, डाकघर और बैंक शाखाओं की स्थापना।

पंडम आयाम	प्रमुख गतिविधि / फोकस	परिचालन पैमाना व मेट्रिक्स	सांस्कृतिक व सामाजिक प्रभाव
सांस्कृतिक मुखरता	पारंपरिक लोक कलाओं, संगीत और व्यंजनों का प्रदर्शन	54,000+ कलाकारों और 1,885 ग्राम पंचायतों की सहभागिता	भय के माहौल से मुक्ति और सामूहिक सांस्कृतिक आत्मविश्वास
विस्तार और विविधता	7 श्रेणियों से बढ़ाकर 12 प्रमुख सांस्कृतिक विधाएं	नृत्य, नाटक, हस्तशिल्प, औषधि ज्ञान और क्षेत्रीय साहित्य शामिल	आदिवासी विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण
विकास का अभिसरण	शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और आजीविका योजनाओं का प्रसार	बंद स्कूल खुले, नए टावर लगे और धान पर बेहतर MSP सुनिश्चित	सुदूर अंचल तक सुशासन और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच
राष्ट्रीय पहचान	राष्ट्रपति और गृह मंत्री जैसे शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति	बस्तर की पहचान 'बारूद' से बदलकर 'सांस्कृतिक विरासत' करना	राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर के गौरवशाली इतिहास का सम्मान

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्तों के लिए यह आलेख कला एवं संस्कृति, आंतरिक सुरक्षा और जनजातीय सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र I & III (भारतीय संस्कृति — जनजातीय कला, लोक परंपराएं और उत्सव; आंतरिक सुरक्षा — उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सांस्कृतिक पुनरुद्धार और विश्वास बहाली)

- सांस्कृतिक पुनरुद्धार और शांति:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे 'बस्तर पंडम' जैसे उत्सव सुरक्षा अभियानों के पूरक के रूप में कार्य करते हुए जनजातीय समुदायों में अलगाव की भावना को समाप्त करते हैं और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं?
- बॉटम-अप विकास मॉडल:** ग्राम पंचायत स्तर से शुरू होने वाले इस सांस्कृतिक अभियान के माध्यम से सुदूर अंचल के लोगों को विकास और निर्णय प्रक्रिया की मुख्यधारा से जोड़ने के मॉडल को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा बस्तर पंडम दृष्टिकोण: बस्तर पंडम संघर्ष के साये से निकलकर सांस्कृतिक जीवंतता और विकासात्मक गतिशीलता की ओर बढ़ने वाले बस्तर के रूपांतरण का प्रतीक है, जो परंपरा को आधुनिक सुशासन के साथ जोड़ता है।

विषय 12: शांत समाज के लिए शांत मन: योग जीवन शैली के माध्यम से सचेतन जीवन (A PEACEFUL MIND FOR A PEACEFUL SOCIETY: MINDFUL LIVING THROUGH THE YOGIC WAY OF LIFE)

मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, आधुनिक जीवनशैली का तनाव, भगवत गीता का 'समत्वम योग उच्यते', महर्षि पतंजलि के योग सूत्र (चित्तवृत्तिनिरोधः), प्राणायाम व माइंडफुलनेस, और भावनात्मक शिक्षा (लेखक: डॉ. हंसाजी योगेन्द्र, निदेशक, द योगा इंस्टीट्यूट, मुंबई)

- कल्याणकारी योजनाएं और आजीविका:** प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त चावल, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी, घरेलू गैस सिलेंडर, नल जल कनेक्शन, तथा जनजातीय युवाओं के लिए 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र व ऑटो गिग हब का विकास।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: बस्तर पंडम आयाम, पैमाना और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका बस्तर पंडम उत्सव के प्रमुख घटकों, पैमानों और प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

योग और शांति विजन: "एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण केवल कानूनों, संस्थाओं या आर्थिक प्रगति के माध्यम से नहीं किया जा सकता; इसका निर्माण भावनात्मक रूप से स्वस्थ लोगों के माध्यम से भी होना चाहिए। मानसिक कल्याण व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण से गहराई से जुड़ा है।" — डॉ. हंसाजी योगेन्द्र

1. कार्यकारी सारांश एवं मानसिक स्वास्थ्य का संकट

जून 2026 के 'योजना' अंक के दसवें आलेख 'शांत समाज के लिए शांत मन: योग जीवन शैली के माध्यम से सचेतन जीवन' (A Peaceful Mind for a Peaceful Society: Mindful Living Through the Yogic Way of Life) में दुनिया के सबसे पुराने योग केंद्रों में से एक 'द योगा इंस्टीट्यूट, मुंबई' की निदेशक, प्रख्यात योग चिकित्सक और लेखिका डॉ. हंसाजी योगेन्द्र ने विश्लेषण किया है कि कैसे आधुनिक तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बीच मानसिक अशांति, तनाव और अकेलेपन का संकट गहराता जा रहा है।

लेखक रेखांकित करती हैं कि एक शांतिपूर्ण समाज केवल कानूनों या आर्थिक विकास से नहीं बनता, बल्कि इसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित नागरिकों की आवश्यकता होती है। जब व्यक्तियों में निराशा, गुस्सा और कुंठा अनसुनी रह जाती है, तो वह सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करती है।

2. आधुनिक जीवनशैली की कीमत और योग की परिभाषा

- बाहरी सफलता बनाम आंतरिक अशांति:** आधुनिक जीवन ने सुविधाएं और अवसर तो दिए हैं, लेकिन साथ ही तुलना, अति-उत्तेजना और भावनात्मक थकान को भी बढ़ाया है। मनुष्य मशीनों को संभालना सीख गया है, लेकिन अपने मन को संभालना भूल रहा है?
- समत्वम योग उच्यते:** भगवत गीता (2.48) के अनुसार 'समत्वम योग उच्यते' यानी समता या संतुलन ही योग है?
- चित्तवृत्तिनिरोधः:** महर्षि पतंजलि के योग सूत्र (1.2) के अनुसार 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' अर्थात् मन की वृत्तियों या उतार-चढ़ाव को शांत करना ही योग है।

3. आंतरिक संतुलन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण

- **प्राणायाम और श्वास नियंत्रण:** श्वास और मन गहरे रूप से जुड़े हैं। प्राणायाम तंत्रिका तंत्र (nervous system) को शांत करता है और भावनात्मक स्थिरता लाता है ?
- **वैज्ञानिक समर्थन:** हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और NIH के शोध बताते हैं कि योग और ध्यान तनाव हार्मोन को कम करते हैं, नींद सुधारते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाते हैं।

4. भावनात्मक शिक्षा और सामाजिक सद्भाव

वेलनेस आयाम	प्रमुख योगिक दर्शन / अभ्यास	शारीरिक व मानसिक प्रक्रिया	दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव
मानसिक संतुलन	भगवत गीता का 'समत्वम' और पतंजलि का 'चित्तवृत्तिनिरोधः'	मन के उतार-चढ़ाव को शांत करना और स्थिरता लाना	तनाव मुक्त जीवन और भावनात्मक परिपक्वता
प्राणायाम व श्वास	सचेत श्वास नियमन और ध्यान अभ्यास	तंत्रिका तंत्र को आराम देना और तनाव हार्मोन घटाना	बेहतर नींद, स्पष्ट सोच और मानसिक ऊर्जा
भावनात्मक शिक्षा	स्कूलों और कार्यस्थलों में योग व माइंडफुलनेस	युवाओं में आत्म-जागरूकता और तनाव प्रबंधन का विकास	आंतरिक रूप से मजबूत और जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण
सामाजिक सद्भाव	योग आधारित जीवनशैली (संयम, संतुलन और संतोष)	व्यक्तिगत शांति को सामूहिक सद्भाव से जोड़ना	हिंसा मुक्त समाज और मजबूत राष्ट्रीय एकता

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख मानसिक स्वास्थ्य, नीति निर्माण और नैतिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & IV (स्वास्थ्य — मानसिक स्वास्थ्य और निवारक देखभाल; नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि — आंतरिक शांति, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता)

- **मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव:** यह आलेख विश्लेषण करता है

- **शिक्षा में भावनात्मक संतुलन:** आधुनिक शिक्षा बुद्धि का विकास करती है लेकिन भावनाओं की उपेक्षा करती है। स्कूलों और कार्यस्थलों पर योग-आधारित भावनात्मक कल्याण कार्यक्रमों को शामिल करना आवश्यक है ?
- **सामूहिक शांति:** एक शांत मन कभी हिंसा या नफरत को बढ़ावा नहीं देता। व्यक्तिगत स्तर का मानसिक संतुलन ही सामूहिक सामाजिक सद्भाव की नींव बनता है।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: योग और मानसिक कल्याण आयाम

नीचे दी गई तालिका योग जीवनशैली के घटकों, मानसिक प्रक्रियाओं और उनके सामाजिक प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

कि कैसे व्यक्तिगत मानसिक कल्याण (mental wellness) सामाजिक शांति और राष्ट्रीय विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है ?

- **योग आधारित भावनात्मक शिक्षा:** आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बौद्धिक विकास के साथ-साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) के समावेश के लिए योग और माइंडफुलनेस के महत्व को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा योग दृष्टिकोण: एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण केवल कानूनों या आर्थिक विकास से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ नागरिकों की आवश्यकता होती है।